



International Journal of Applied Research

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; SP7: 98-100

डॉ अंकुर अग्रवाल
एसिओ प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
रमा जैन कन्या महाविद्यालय,
नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

डॉ शिवाली चौहान
एसिओ प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
रमा जैन कन्या महाविद्यालय,
नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

Editors

Dr. Parmil Kumar
(Associate Professor),
Sahu Jain (P.G) College,
Najibabad (Bijnor), Uttar
Pradesh, India

Faiyazurehman
(Research Scholar),
Dr. Bhimrao Ambedkar
University, Agra), Uttar
Pradesh, India

Dr. Anurag
(Principal),
Baluni Public School
Tallamotadak, Najibabad),
Uttar Pradesh, India

Corresponding Author:
डॉ अंकुर अग्रवाल
एसिओ प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
रमा जैन कन्या महाविद्यालय,
नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

(Special Issue)
“Twenty-First Century: Cultural and Economic Globalization”

कोविड 19 का आर्थिक वैश्वीकरण पर प्रभाव

डॉ अंकुर अग्रवाल एवं डॉ शिवाली चौहान

DOI: <https://doi.org/10.22271/allresearch.2021.v7.i7Sc.8686>

सारांश

वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ स्थानीय वस्तु या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया से है। जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर का समाज बनाते हैं और एक साथ कार्य सम्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक समूह है। वैश्वीकरण का उदय अस्सी के दशक में हुआ था, परन्तु इसकी अवधारणा अति प्राचीन काल से ही मानव समाज में विकसित थी। भूमंडलीकरण जिस बाजारवाद की विदेशना करना है उसका आधुनिक स्वरूप भारत में सन् 1991 के आर्थिक उदारीकरण एवं खुले बाजार की नीति के तहत सामने आया। इसका उद्देश्य न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था बल्कि वैश्वीकरण स्तर पर भारत को आर्थिक रूप में विकसित करना भी था। वैश्वीकरण से गरीबी उन्मुलन, बेरोजगारी में कमी, श्रम में पारदर्शिता एवं अनेक क्षेत्रों में बेहतरी की परिकल्पना की गयी थी। कोविड-19 का आर्थिक वैश्वीकरण पर प्रभाव एवं अनेक क्षेत्रों में बेहतरी की परिकल्पना की गयी थी। कोविड-19 का आर्थिक वैश्वीकरण पर प्रभाव का विश्लेषणकरना है, जिसमें इसके आर्थिक प्रभाव, आयात पर प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव एवं सकारात्मक पक्ष सम्मिलित है। आर्थिक वैश्वीकरण पर कोविड-19 का कितना गहरा असर पड़ेगा ये दो बातों पर निर्भर है, प्रथम आने वाले समय में कोविड-19 की समस्या भारत में कितनी गम्भीर है और द्वितीय इस पर भारत में नियंत्रण कब तक पाया जा सकता है? वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के सम्बन्ध में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूँजी प्रवाह, और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण। वैश्वीकरण ने पूरे विश्वभर में लोगों के लिए महान अवसरों का निर्माण किया है। इसने समाज में लोगों की जीवन-शैली और स्तर में बड़े स्तर पर बदलाव किया है। यह विकासशील देशों या राष्ट्रों के लिए विकसित होने के बहुत से अवसरों को प्रदान करता है। वैश्वीकरण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से परम्परा, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक विकास, जीवन शैली, समृद्धि आदि को प्रभावित करता है।

कूटशब्द: कोविड-19, वैश्वीकरण, बेरोजगारी, पूँजी प्रवाह, सकारात्मक, नकारात्मक इत्यादि।

प्रस्तावना

विज्ञान और वैज्ञानिक उपलब्धियों ने मानव समाज को कई वरदानों से अभिभूत किया है किन्तु भविष्य के गर्भ में पनप रहे अभिशापों से अनभिज्ञ होकर उसे अपनी सफलता मानकर हम मुस्कुराते रहे। यह धरा जो जन-जीवन से परिपूर्ण है उसे विनाश के पथ पर अग्रसर करने में कहीं न कहीं हम जिम्मेदार हैं। वैश्विक महामारी कोई पहली बार नहीं हुई है किन्तु वैश्विकरण के कारण एवं इस बार इसके फैलने का अनुपात कहीं ज्यादा है।

उद्देश्य

1. कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियां का अध्ययन।
2. कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभावों का अध्ययन।
3. आर्थिक वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव एवं सकारात्मक पक्ष।
4. कोविड-19 से वैश्विक अर्थव्यवस्था का विद्यन।

कोविड-19 और भारत

वर्तमान कोविड-19 वायरस से संपूर्ण विश्व ग्रसित है तथा एक अनियन्त्रित वायरस है, जिसे वैश्विक संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है। नवंबर 2019 में यह चीन की लैब से निकलकर

धीरे-धीरे यह वायरस इसान से इसान में फैलने लगा और देखते ही देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिये। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना वायरस का सर्वप्रथम केस दक्षिण भारत के केरल में सामने आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 19 मार्च को जनता से अपील की कि 21 मार्च को जनता कफ्यू में अपना पूर्ण सहयोग दें। 21 मार्च 2020 को जनता कफ्यू लगा जिसमें भारत की जनता ने अपना संपूर्ण योगदान दिया, फिर प्रधानमंत्री मोदीजी ने 24 मार्च 2020 को कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च 2020 से 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। 15 अप्रैल सुबह 10:00 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाकर 3 मई करने का फैसला लिया। 4 मई 2020 से 17 मई तक तृतीय लॉकडाउन लगा फिर चतुर्थ लॉकडाउन 10 मई से 31 मई तक रहा। इसी तरह लॉकडाउन का पाँचवा चरण 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक रहा। इसी लॉकडाउन की अवधि में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविकाओं ने घर पर रहकर ही मास्क तैयार किये, अपने निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामवासियों को जागरूक किया तथा साथ ही पोस्टर, गीत, कविताओं के माध्यम से कोविड-19 से बचाव हेतु सार्थक संदेश दिया।

आर्थिक चुनौतियां

कोविड-19 के कारण देशभर में कफ्यू है, सभी फैक्ट्री, कार्यालय, मॉल्स, उद्योग-धर्चे, मैट्रो इत्यादि बंद हैं। घरेलू आपूर्ति और मांग प्रभावित होने से आर्थिक वृद्धि दर पर असर हो रहा है। वहीं जोखिम बढ़ने से घरेलू निवेश में सुधार में भी देरी होने की संभावना प्रकट हो रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर में पहुँच सकती है। कोविड-19 ने न केवल भारत की बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में कमी कर रखी है। कोविड-19 के कारण भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ा है, कोरोना से भारत की आर्थिक वृद्धि दर में भारी कमी आयी है। दुनिया भर में बचत और राजस्व के रूप में जमा खरबों डॉलर स्वाहा हो चुका है। वैशिक जीडीपी में रोज कमी दर्ज की जा रही है, लाखों लोग अपना रोज़गार खो चुके हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है कि 90 देश उससे मदद मांग रहे हैं। आईएलओ के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में ढाई करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रयासों से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे सार्वजनिक खर्च में भारी कटौती हुई है। लॉकडाउन के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन और तैयार उत्पादों के वितरण की श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिसे पुनः शुरू करने में कुछ समय लग सकता है। रेस्टोरेंट्स बंद हैं, लोग घूमने नहीं निकल रहे, नया सामान नहीं खरीद रहे लेकिन, कम्पनियों को किराया, वेतन और अन्य खर्चों को भुगतान तो करना ही है। ये नुकसान झेल रही कम्पनियां ज्यादा समय तक भार सहन नहीं कर पाएंगी और इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ेगा। सम्पूर्ण लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था थम गई। हमारे देश में छोटे-छोटे कारखाने और लघु उद्योगों की बहुत बड़ी संख्या है, उन्हें नकदी की समस्या हो जाएगी क्योंकि उनकी आय नहीं होगी, ये लोग बैंक के पास भी नहीं जा पाते हैं इसलिए ऊँचे ब्याज पर कर्ज़ ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं।

अनौपचारिक क्षेत्रों में फेरी वाले, विक्रेता, लघु उद्योग और व्यापार समिलित हैं। इस वर्ग में सरकार के पास टैक्स नहीं आता। लॉकडाउन और कोविड-19 के दौर में पर्यटन, होटल सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। यह स्थिति सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है, जो उसके सामने एक विशाल समस्या आ खड़ी हुई है। 2008 के दौर में कुछ कम्पनियों को आर्थिक मदद

देकर संभाला गया। आज अगर सरकार ऋण दें तो उसे सभी को देना पड़ेगा, हर सेक्टर में उत्पादन और खरीदारी प्रभावित हुई है। कोविड-19 का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। विकासशील और विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसके सामने लाचार हो गयी हैं। भारत में विदेशी निवेश के द्वारा अर्थव्यवस्था मजबूत करने की कोशिशों में भी कमी आई है। विदेशी कम्पनियों के पास निवेश करने हेतु पर्याप्त धन नहीं है। अर्थव्यवस्था का कोविड-19 में कितना गहरा असर पड़ेगा ये दो बातों पर निर्भर करता है कि प्रथम कोरोना वायरस भारत में कितना गम्भीर है और द्वितीय कब तक सरकार द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है।

आर्थिक वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव

कोविड-19 महामारी और वैशिक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के अध्ययन ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस महामारी ने सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर दिया है तथा भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभवित कर रही है।

- कोरोना वायरस हवाई यात्रा, शेयर मार्केट, वैशिक आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है।
- यह वायरस भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, जिससे सम्पूर्ण वैशिक अर्थव्यवस्था सुरक्षी तथा मंदी का कारण बन सकती है।
- शेयरधारक द्वारा बाजारों से बाहर निकलने के कारण शेयर बाजार सूचकांक में लगातार गिरावट आ रही है। लोग बड़ी राशि को सुरक्षित क्षेत्रों में लगा रहे हैं जिससे कीमतों में तेजी व उत्पादकता में कमी आ रही है।
- निवेशक ऐसे समय में सामान्यत खर्च में निवेश करते हैं, इस महामारी के दौरान उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया है जिससे सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है तथा निवेशकों ने सरकारी गांरंटी युक्त ऋण पत्रों एवं अंशों आदि में अधिक निवेश करना उचित समझा।

आर्थिक वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव एवं सकारात्मक पक्ष

लॉकडाउन के कारण पिछले दो माह में अर्थव्यवस्था बंद ही पड़ी है। इन दो महीनों में केवल 50 फीसदी आर्थिक गतिविधियां ही हुई हैं। तब भी पूरे वित्तीय वर्ष में एक महीने की आर्थिक गतिविधि नष्ट हो चुकी हैं और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के खुलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्थव्यवस्था आने वाले महीनों में धीरे-धीरे खुलती जाएगी लेकिन महामारी कोविड-19 का नकारात्मक आर्थिक प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाएगा। अर्थव्यवस्था की समस्या न केवल आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करेगी, बल्कि यह भारत के उद्योग-धर्चों, कारखानों, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल एवं अन्य उद्योगों को गम्भीर रूप से प्रभावित करेगी। निर्यात, जिसे अर्थव्यवस्था के विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, इसमें वैशिक मंदी की स्थिति में और भी गिरावट आ सकती है, साथ ही निवेश में भी गिरावट देखी जा सकती है। वायरस द्वारा यह संकट किसी अन्य वित्तीय संकट से बिल्कुल अलग है। अन्य वित्तीय संकटों का समाधान समय-रहते उपायों द्वारा किया जा सकता है परन्तु वायरस जैसे संकट का समाधान इन वित्तीय उपायों द्वारा किया जाना संभव नहीं है।

आर्थिक वैश्वीकरण का सकारात्मक पक्ष यह है कि भारतीय कम्पनियों चीन आधारित वैशिक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल प्रमुख भागीदार नहीं हैं अतः भारतीय कम्पनियां इससे अधिक प्रभावित नहीं होंगी एवं कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आ रही है जो कि बृहद अर्थव्यवस्था और उच्च मुद्रा स्फीति के चलते अच्छी सूचना का प्रतीक है। कोविड-19 महामारी के समय में हमें देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के कुछ शुरूआती संकेत देखने को मिले हैं। मई महीने के आर्थिक गतिविधियों के सूचकांक, जैसे कि

ईंधन की खपत, बिजली का इस्तेमाल, खुदरा वित्तीय लेन-देन की संख्या और मात्रा, पूरे देश में सामानों की आवाजाही, ई-वे बिल और हाईवे पर टोल का संग्रह, ये सभी सूचकांक इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं।

वैशिक अर्थव्यवस्था का विद्युत

महामारी ने वैशिक स्तर पर अभूतपूर्व स्वास्थ्य चुनौतियों को उठाया और अद्वितीय नीतिगत दुविधाएं पैदा की। वैशिक उत्पादन में वृद्धि की गति कमजोर पड़ने के कारण व्यापार तनाव, राजनीतिक अस्थिरता, धीमी मांग और औद्योगिक गतिविधि में कमी जैसे विभिन्न कारकों के कारण थी। कोविड-19 महामारी ने गंभीर मांग और आपूर्ति में विच्छेद पैदा करके मंदी को बढ़ा दिया है। महामारी के बाद की आर्थिक संभावनाओं और नीतियों के बारे में अनिश्चितता ने निवेश की गति को रोक दिया है और शिक्षा में व्यवधानों ने मानव पूँजी संचय को कम कर दिया है। ग्लोबल लॉकडाउन के कारण विश्व आर्थिक गतिविधियों में ठहराव आ गया है तथा उत्पादन में भारी गिरावट आई है। वैशिक उत्पादन में एक सदी में सबसे तेज संकुचन देखने की उम्मीद है जिसमें अनुबंध किया जा रहा है। विश्व बैंक और आई एमएफ द्वारा क्रमशः प्रदान किए गए अनुमानों के अनुसार 2020 में 3.5–4.3 प्रतिशत की श्रेणी में संकुचन देखा गया है। 2020 और 2021 में वैशिक जीडीपी का संचयी नुकसान लगभग 9 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर आंका गया है—जापान और जर्मनी की संयुक्त अर्थव्यवस्थाओं से अधिक। वर्ष के जुलाई–सितम्बर 2020 तिमाही में लॉकडाउन को आसान बनाने और आर्थिक गतिविधि में पुनरुत्थान के साथ वैशिक विकास के अनुमानों को वर्ष के माध्यम से ऊपर की ओर संशोधित किया गया था। महामारी से प्रेरित सीमा बंद होने और आपूर्ति बाधित होने से वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान में बाधा उत्पन्न हुई। वैशिक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक जुलाई 2020 से पहले पांच महीने के लिए संकुचित में था। वैशिक व्यापार को 2020 में 9.2 प्रतिशत तक अनुबंधित करने का अनुमान है। 2009 की वैशिक मंदी के दौरान गिरावट के साथ तुलनात्मक रूप से लेकिन अर्थव्यवस्थाओं की एक बड़ी हिस्सेदारी को प्रभावित किया है। व्यापार ने महामारी का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, जिससे देशों को जीवनप्रद भोजन और चिकित्सा आपूर्ति तक सुरक्षित पहुंच मिल सकती है।

महामारी ने वैशिक ऋण संचय की एक दशक लम्बी लहर के साथ जुड़े जोखिमों को बढ़ा दिया है। बड़े पैमाने पर विवेकाधीन समर्थन, आउटपुट में तेज संकुचन और राजस्व में भारी गिरावट के कारण सरकारी ऋण और घाटे में वृद्धि हुई। ऋण बोझबढ़ गया है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने तेजी से कम बिक्री की अवधि का सामना किया है और सम्पन्न लोगों ने बड़े प्रोत्साहन पैकेजों को वित्तपोषित किया है। ऋण का स्तर ऐतिहासिक ऊवाईयों पर पहुंच गया है, जिससे वैशिक अर्थव्यवस्था विशेष रूप से वित्तीय बाज़ार तनाव के प्रति कमजोर हो गई है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य सरकारी ऋण 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान बढ़ा। ऋण में और वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि सरकारें और वित्तीय प्रणालियां पूँजी, श्रम, कौशल और नवाचार के बाद के आर्थिक माहौल में बदलाव की सुविधा देकर वसूली को वित्त प्रदान करती है।

निष्कर्ष

कोरोना वायरस ने न केवल भारत की बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोनो वायरस के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। कोरोना से भारत की आर्थिक

वृद्धि दर में गिरावट आयी है। भारत सरकार को लगातार विकास की गति का अवलोकन करने की आवश्यकता है, साथ ही चीन पर निर्भर भारतीय उद्योगों को आवश्यक समर्थन एवं सहायता प्रदान करनी चाहिए। कोरोना वायरस जैसी बीमारी की पहचान, प्रभाव, प्रसार एवं रोकथाम पर चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जानी चाहिए ताकि इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही समय पर वित्तीय पूँजी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना बेहद अहम होगा। सरकार को भारत के वित्तीय सेवाओं के सेक्टर के लिए मिशन 5 गुण 5 की स्थापना करनी चाहिए जिसका मक्सद पांच साल में 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनोमी के लक्ष्य को हासिल करना होना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार को उन संस्थानों को बढ़ावा देना चाहिए, जो राष्ट्र निर्माण के इस मिशन में सर्वाधिक योगदान दे रहे हैं। हमें उद्यमियों का होसला बढ़ाने वाले कदम उठाने होंगे, उन्हें सरकार को ये संदेश देना होगा कि भारत में काम करना अब सबसे आसान होगा।

संदर्भ

1. "The IMF said, Kovid-19 consistently spread the risk for the Indian economy". Hindustan Live. Retrieved 25 July 2020.
2. "6 Factor" which shows that reforms have started in the country's economy". Navbharat Times. Retrieved 25 July 2020.
3. दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, जनवाणी, विभिन्न तिथियों से सम्बन्धित
4. आर्थिक समीक्षा 2020–21, खण्ड–2
5. <https://www.covid19india.org/>
6. <https://prsindia.org/covid-19/cases>
7. https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_recession_in_India
8. www.orfonline.org
9. www.drishtiias.com